



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050



+918988886060

www.vajiraoinstitute.com



info@vajiraoinstitute.com

YOJANA MAGAZINE ANALYSIS

(योजना पत्रिका विश्लेषण)

(वर्ष भर का पुनरावलोकन)

(December 2024)

(Part III)

TOPICS TO BE COVERED

- भारतीय कृषि के समग्र विकास की दिशा में सार्थक प्रयास
- जलवायु परिवर्तन पर सरकार के न्यास: विकसित भारत@2047 के लिए स्थायी समाधान

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050
+918988886060



www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com



भारतीय कृषि के समग्र विकास की दिशा में सार्थक प्रयासः

परिचयः

- वर्ष 2024 में कृषि के समावेशी विकास और किसानों के कल्याण के लिए छह सूत्री

कार्यनीति का अनावरण किया गया।

भारतीय कृषि को भविष्य के लिए तैयार

और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के

लिए चल रही योजनाओं को अत्याधुनिक

तकनीकों के साथ और मजबूत किया

गया।



- पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों का

समाधान/शमन करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और उसके बाद इसका विस्तार,

प्रमुख जोर वाले क्षेत्रों में से एक रहा है। छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं और

युवा अपने वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण के लिए कृषि के सभी क्षेत्रों में

फोकस में रहे।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



बजट 2024-25 में कृषि के लिए ऐतिहासिक आबंटन:

- बजट में प्रस्तावित भविष्य की पहलों का समर्थन करने के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक उच्च आबंटन हासिल किया और इसने कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया।
- कृषि अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और सक्षम मानव संसाधन विकसित करने के लिए आबंटन को बढ़ाकर 9,941.09 करोड़ रुपये कर दिया गया।
- कृषि के संबद्ध क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को 4,521 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जबकि मत्स्य पालन क्षेत्र को 2,616 करोड़ रुपये का अनुदान मिला। यह आवंटन मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के विकास को सुविधाजनक बनाकर डेयरी, पशुधन और मत्स्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए है।

कृषि के उत्पादन से जुड़े आंकड़े:

- इस वर्ष (2023-24) 332.3 MMT (मिलियन मीट्रिक टन) का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हासिल किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.61 MMT अधिक है। यह उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से चावल (137.825 MMT), गेहूं (113.292 MMT) और श्री अन्न (17.572 MMT) के अधिक उत्पादन के कारण हुई है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- तिलहनों में, मिशन मोड में विशेष पहल के कारण सफेद सरसों और सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल किया गया। 2023-24 के दौरान दालों का राष्ट्रीय उत्पादन 163.23 लाख टन (2015-16) से बढ़कर 244.93 लाख टन हो गया है।
- वर्ष 2023-24 में फलों का उत्पादन 2022-23 की तुलना में 2.29 प्रतिशत बढ़कर 112.73 मिलियन टन होने की उम्मीद है। सब्जियों का उत्पादन लगभग 205.80 मिलियन टन रहने का अनुमान है।

सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि:

- विपणन सीजन 2024-25 और 2025-26 के लिए क्रमशः सभी अनिवार्य खरीफ और रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की गई। सभी फसलों में, यह वृद्धि अखिल भारतीय भारत औसत उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना MSP तय करने की सरकार की नीति के अनुरूप है।
- हालांकि, खरीफ फसलों के घोषित MSP में उत्पादन की औसत लागत पर अपेक्षित मार्जिन सबसे अधिक बाजरा (77 प्रतिशत) के मामले में था। रबी फसलों के घोषित MSP के मामले में उत्पादन की औसत लागत पर अपेक्षित मार्जिन सबसे अधिक गेहूं (105 प्रतिशत) के लिए था।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- बढी हुई MSP किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करती है और फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा देती है। हाल के वर्षों में, दालों, तिलहनों और पोषक अनाज (श्री अन्न) के लिए उच्च MSP की पेशकश करके अनाज के अलावा अन्य फसलों की खेती को बढ़ावा दिया गया है।

कृषि के समग्र विकास के लिए सात प्रमुख योजनाओं को मंजूरी:

- केंद्र सरकार ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सात प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी।
- 'डिजिटल कृषि मिशन' सबसे प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य किसान-केंद्रित डिजिटल समाधान प्रदान करके कृषि क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन करना है। इस मिशन के तहत तीन प्रकार के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) बनाए जाएंगे, जैसे कि एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (KDSS) और मृदा प्रोफाइल मैपिंग।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रति तैयार करने और सतत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा बनाए रखने के लिए 3,979 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एक विशेष पहल को मंजूरी दी गई।
- सात की सूची में अन्य योजनाओं में कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना (कुल 2,291 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ); टिकाऊ पशुधन

ADDRESS:



स्वास्थ्य और उत्पादन (1,702 करोड़ रुपये); 1,202 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'कृषि विज्ञान केंद्र' (कृषि विस्तार केंद्र) को मजबूत करना; प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (1,115 करोड़ रुपये); और बागवानी का सतत विकास (860 रुपये)।

- कृषि शिक्षा को मजबूत करने की योजना छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों के लिए तैयार करेगी और उन्हें सिखाएगी कि कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक का उपयोग कैसे करें।

कृषि के समग्र विकास की छह सूत्री कार्यनीति:

- सरकार ने छह सूत्री कार्यनीति अपनाकर कृषि के समग्र विकास और किसानों के सामाजिक कल्याण पर अपना जोर फिर से बढ़ाया है। उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन लागत में कमी, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई, कृषि का विविधीकरण और मूल्य संवर्धन तथा प्राकृतिक खेती कार्यनीति के प्रमुख क्षेत्र हैं।
- डिजिटल पहल के तहत, देश भर में कृषि कीट निगरानी और कीट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (NPSS) शुरू की गई है। NPSS ऐप पर 22,300 से अधिक सर्वेक्षण भी किए गए हैं।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- खेतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक विशेष कदम के रूप में, प्रधानमंत्री ने 61 फसलों की 109 किस्में जारी कीं, जिनमें 34 खेत की फसलें और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं। इन किस्मों को ICAR (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) द्वारा जलवायु परिवर्तन, प्रकृति की अनिश्चितता, कीटों के हमले, पोषण संबंधी कमियों आदि जैसी नई चुनौतियों से निपटने के लिए विकसित किया गया है।
- कृषि मंत्रालय ने किसानों को किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण बीज प्राप्त करने में मदद करने के लिए SATHI (बीज प्रमाणीकरण, पता लगाने की क्षमता और समग्र सूची) पोर्टल पर 266 प्रजनक बीज-उत्पादन केंद्रों को शामिल किया है।
- सरकार ने किसानों के साथ संचार और संपर्क को मजबूत करने के लिए एक नया टीवी और रेडियो कार्यक्रम 'कृषि चौपाल' शुरू करने का फैसला किया है।
- किसानों को सब्सिडी, इनपुट आपूर्ति, सेवाओं, कार्यक्रमों, योजनाओं आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपने प्रश्नों या शिकायतों को दर्ज करने में सहायता के लिए एक बहु-चैनल सहायता के रूप में जल्द ही एक अनूठी किसान शिकायत निवारण प्रणाली (FGRS) की शीघ्र ही शुरुआत होगी।

ADDRESS:



किसानों के कल्याण की अन्य पहलें:

- इस वर्ष, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के कवरेज को और बढ़ाने के लिए, संबंधित बैंक शाखाओं के माध्यम से KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) खाताधारक किसानों को संतुष्ट करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इसके परिणामस्वरूप, खरीफ 2024 के लिए बीमित किसानों की कुल संख्या 293 लाख के सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है।
- कृषि अवसंरचना कोष की योजना के तहत, कृषि मंत्रालय ने अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत 7,000 से अधिक बुनियादी ढांचा इकाइयां बनाने, 5,500 करोड़ रुपये की कुल ऋण राशि और विभिन्न परियोजनाओं और परिसंपत्तियों के लिए 7,500 करोड़ रुपये का निवेश जुटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
- सरकार ने 25 लाख से अधिक नए किसानों को जोड़ने के लिए पीएम-किसान योजना के तहत संतुष्टि अभियान शुरू किया। इस प्रकार, लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 9.51 करोड़ किसानों के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है।

टिकाऊ कृषि के विकास पर बल:

- टिकाऊ कृषि के एक प्रमुख घटक के रूप में, सरकार ने अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान का

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



प्रस्ताव दिया है। इस पहल का समर्थन करने के लिए, किसानों को सीधे विशिष्ट इनपुट की आपूर्ति की सुविधा के लिए देश भर में 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

- वर्ष 2023-24 से, एक अलग और स्वतंत्र योजना के रूप में 'प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन' पहले से ही चल रहा है। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, मूल्य संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किसान उत्पादक संगठनों, कृषि-सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
- कुल मिलाकर, वर्ष 2024 में एक कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्गठन और निर्माण हुआ, जो सभी वर्गों और श्रेणियों के किसानों की भलाई सुनिश्चित करते हुए भारतीय कृषि को भविष्य के लिए तैयार करने का प्रयास करता है।

भारत की पहली एकीकृत कृषि-निर्यात सुविधा:

- सरकार ने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई में भारत की पहली एकीकृत कृषि-निर्यात सुविधा के निर्माण को मंजूरी दी है। यह कृषि-लॉजिस्टिक्स में क्रांति लाने और अपव्यय को कम करने के लिए 284.19 करोड़ रुपये की PPP परियोजना है।
- यह सुविधा लॉजिस्टिक्स में अक्षमताओं को दूर करेगी, कई प्रकार की हैंडलिंग को कम करेगी और कृषि उत्पादों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाएगी। इसके अलावा, इससे किसान सशक्त होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निर्यात क्षमता बढ़ेगी।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



जलवायु परिवर्तन पर सरकार के न्यास: विकसित भारत@2047 के लिए स्थायी समाधान

परिचय:

- भारत, विश्व में सर्वाधिक गति से विकास करने वाले देशों में से एक है, जिसके समक्ष जलवायु परिवर्तन के बढ़ते जोखिम से निपटने और उसके अनुकूल ढलने के साथ-साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का भी दायित्व है।
- भारत अपने विविध पारिस्थितिकी तंत्रों और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के कारण जलवायु प्रभावों के प्रति अतिसंवेदनशील है तथा इन मुद्दों से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति अपनाई है। भारत सरकार ने समय-समय पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, जलवायु प्रभावों से निपटने के प्रति ठोस कदम उठाने और शहरी, ग्रामीण और औद्योगिक परिवेश में टिकाऊ कार्यप्रणालियों को शामिल करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं।



ADDRESS:



- हाल ही में इन पहलों ने काफी प्रगति हासिल की है जिसे साँवरेन ग्रीन बॉन्ड, मिष्ठी और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जैसे प्रमुख कार्यक्रमों में देखा गया है। ये कार्यक्रम एक ऐसे भविष्य का आधार होंगे, जो पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल और लचीला होगा।

NDC लक्ष्य और भारत की उपलब्धियां:

- 2015 में अपनाए गए भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के अनुसार देश ने 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर की तुलना में 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने और 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों से लगभग 40 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
- ये दोनों उद्देश्य समय सीमा से बहुत पहले ही पूरे हो गए हैं। 31 मई, 2024 तक गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों से कुल स्थापित विद्युत शक्ति क्षमता कुल संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता का 45.40 प्रतिशत थी। 2005 से 2019 तक इसके सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 33 प्रतिशत की गिरावट आई है।
- अगस्त, 2022 में भारत ने अपने NDC में संशोधन किया, 2005 के आधार रेखा से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक

ADDRESS:



कम करने का लक्ष्य बढ़ाया और गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों से संचयी स्थापित विद्युत शक्ति क्षमता के लक्ष्य को 2030 तक 50 प्रतिशत तक बढ़ाया।

- भारत ने जलवायु परिवर्तन से सम्बद्ध सौर ऊर्जा उत्पादन में पर्याप्त प्रगति हासिल की है। 30 अप्रैल, 2024 तक कुल सौर ऊर्जा उत्पादन 82.64 गीगावाट तक पहुंच गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जलवायु लचीलापन, कार्बन पृथक्करण और स्थिरता में सुधार पर केंद्रित कई महत्वपूर्ण पहलों को क्रियान्वित किया गया।

पीएम सूर्य घर योजना:

- 'पीएम सूर्य घर योजना' जिसे मुफ्त बिजली योजना कहा जाता है का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी, 2024 को किया था। इसका कुल बजट 75,021 करोड़ रुपये है।
- इस पहल का उद्देश्य पूरे भारत में एक करोड़ आवासीय घरों की छतों पर सौर पैनल लगाना है जिससे हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की आपूर्ति की जा सके।
- इसका उद्देश्य परिवार के बिजली पर आने वाले खर्च को कम करना है और साथ ही उन्हें अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करने और ग्रिड को वापस बेचने की सुविधा देकर संधारणीय ऊर्जा पद्धतियों को बढ़ावा देना है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- इस कार्यक्रम के तहत गृहस्वामी 2 केवी सौर स्थापना के लिए लागत का 60 प्रतिशत और 3 केवी तक के लिए 40 प्रतिशत तक केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) प्राप्त कर सकते हैं जिसकी अधिकतम सीमा 78,000 रुपये है।
- इस प्रयास का उद्देश्य सौर क्षमता को 30 गीगावाट तक बढ़ाना है, जिसके परिणामस्वरूप बिजली के खर्च में उल्लेखनीय कमी आएगी और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जाएगा जिसका लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता हासिल करना है।
- इसके अलावा इस योजना से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 1.7 मिलियन से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है।

सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड: जलवायु से संबंधित क्रियाकलापों का वित्तपोषण

- भारत ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करके पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ गतिविधियों को वित्तपोषित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत सरकार पर्यावरण संवर्धन परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने के लिए 'ग्रीन बॉन्ड' नामक ऋण उपकरण जारी करती है।
- भारत ने 2024 में जारी किए गए ग्रीन बॉन्ड की शुरुआती किश्त से 8,000 करोड़ रुपये हासिल किए। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पहलों को वित्तपोषित करने के लिए 16,000

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है जो जलवायु की प्रतिरोधी क्षमता में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क वित्तपोषण के लिए आवश्यक क्षेत्रों को रेखांकित करता है जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन, बायोमास), जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और प्रदूषण शमन शामिल हैं।
- भारत द्वारा ग्रीन बॉन्ड को अपनाना एक रणनीतिक वित्तीय पहल और पेरिस समझौते और कॉप 26 जैसे वैश्विक जलवायु सम्मेलनों में स्थापित दायित्वों के पालन का एक अंतरराष्ट्रीय संकेत दोनों है।
- इसके बावजूद ग्रीन बॉन्ड पर रिटर्न के बारे में जोखिम की बढ़ती धारणा और अपर्याप्त डेटा जैसी बाधाएं बनी हुई हैं जिनके समाधान की आवश्यकता है, जिससे इनकी सफलता निरंतर कायम रहे।

गोवरधन पहल: मवेशियों से नकद लाभ

- सरकार की गोवरधन (गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना का उद्देश्य 2023-24 के बजट में घोषित 500 नई बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से कचरे को धन में बदलना है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- ये संयंत्र बड़े पैमाने पर मवेशियों के गोबर और अन्य जैविक कचरे को बायोगैस में बदल देंगे जो एक हरित ऊर्जा स्रोत है। इस प्रयास द्वारा अनुपचारित जैविक कचरे से मीथेन उत्सर्जन कम होता है।
- यह योजना एक चक्रीय अर्थव्यवस्था के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करके और जैविक खाद और जैव उर्वरकों सहित जैव-उत्पादों और उप-उत्पादों के व्यवसायीकरण के माध्यम से आर्थिक अवसर पैदा करके स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देता है।

महत्वपूर्ण खनिज मिशन:

- भारत ने अपने 2024-25 के बजट के तहत एक महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया है जिसका लक्ष्य स्थानीय उत्पादन को बढ़ाना और तांबा और लिथियम जैसे आवश्यक खनिजों का पुनर्चक्रण करना है। ये खनिज रक्षा, कृषि, ऊर्जा, औषधि और दूरसंचार जैसे उद्योगों के लिए आवश्यक हैं। फिर भी वे अपनी सीमित उपलब्धता और चुनिंदा स्थानों में संकेन्द्रण के कारण आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े जोखिमों का सामना करते हैं।
- इस मिशन का महत्व घरेलू उत्पादन और पुनर्चक्रण को बढ़ाने, आवश्यक खनिजों को चिह्नित करने, आयात निर्भरता को कम करने, अन्वेषण में तेजी लाने, बाहर से

ADDRESS:



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050
+918988886060



www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com



खनिज प्राप्त करने, संसाधन दक्षता को अनुकूलित करने, खनिजों को पुनर्चक्रित करने और उचित अनुसंधान और विकास के माध्यम से विकल्पों की खोज करने में निहित है।

तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्ठी):

- जून 2023 में आरंभ की गई तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्ठी) एक व्यापक परियोजना है जिसे भारत के सभी तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव पुनर्वनीकरण और संरक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि कार्बन को सोखने और तूफानों और समुद्र के बढ़ते स्तर के खिलाफ प्राकृतिक अवरोधक के रूप में जलवायु परिवर्तन से निपटने में मैंग्रोव आवश्यक है। मिष्ठी की कार्ययोजना 2023-2024 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के दौरान नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 540 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में मैंग्रोव को बहाल करने और पुनर्वनीकरण की है।
- अपने पर्यावरणीय लाभों के अलावा मिष्ठी का एक सामाजिक-आर्थिक पहलू भी है। इस पहल के तहत इकोटूरिज्म, संधारणीय मत्स्य पालन और विभिन्न मैंग्रोव-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर तटीय लोगों की आजीविका सुरक्षा में सुधार वांछित है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



अमृत धरोहर: आर्द्रभूमि के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला

- अमृत धरोहर योजना को केंद्रीय बजट 2023-24 में पूरे देश में आर्द्रभूमि की जैव विविधता में सुधार लाने के लिए आर्द्रभूमि के उपयोग को अधिकतम करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। आर्द्रभूमि के सर्वोत्तम संभव उपयोग को बढ़ावा देने और जैव विविधता, कार्बन भंडारण, इकोटूरिज्म संभावनाओं और स्थानीय समुदाय के आय सृजन में सुधार करने के लिए 2023-24 से शुरू होने वाले अगले तीन वर्षों के दौरान इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा।
- अमृत धरोहर इकोटूरिज्म को बढ़ावा देकर और स्थानीय समुदायों के लिए वैकल्पिक आजीविका का सृजन करके कार्बन अवशोषण और जैव विविधता दोनों के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र, आर्द्रभूमि को बहाल करने और सुरक्षित रखने का प्रयास करता है।

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम: वनीकरण को प्रोत्साहन

- 2023 में शुरू किया गया भारत का ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) वनीकरण और पुनर्वनीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव रणनीति दर्शाता है।
- पर्यावरण मंत्रालय ने अप्रैल 2024 में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) के लिए संशोधित अनुशंसाएं जारी कीं। नए नियम वनीकरण के माध्यम से 'पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली' पर जोर देते हैं।

ADDRESS:



- यह पहल लोगों, उद्योगों और समुदायों द्वारा क्षरित वनभूमि पर पेड़ लगाने को बढ़ावा देती है जिससे बाजार विनिमय के लिए ग्रीन क्रेडिट अर्जित होता है। ये क्रेडिट पर्यावरण पुनर्वास और कार्बन सिंक के संवर्धन में भागीदारी के लिए प्रतिफल के रूप में काम करते हैं।
- यह कार्यक्रम 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की भारत की व्यापक रणनीति का अभिन्न अंग है।
- राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (NAP) और प्रतिपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) आगे की पहल हैं जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को बढ़ाती हैं।

सौर पार्क योजना:

- वर्ष 2014 में शुरू की गई सौर पार्क योजना को वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में सौर पार्क बनाना है, जिससे भारत को 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- यह योजना सरकारों द्वारा अक्षय ऊर्जा अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहित करती है और साथ ही सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को जुटाती है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



VAJIRAO & REDDY INSTITUTE

India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050
+918988886060



www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com



इकोमार्क योजना:

- 26 सितंबर, 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इकोमार्क नियम 2024 अधिसूचित किए। 1991 को इकोमार्क योजना को नए नियमों के साथ लाया गया है। भारत सरकार ने पर्यावरण के लिए लाभकारी वस्तुओं को लेबल करने के लिए इकोमार्क योजना शुरू की। इस योजना का प्रबंधन भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा किया जा रहा है और इसमें साबुन और डिटर्जेंट, पेंट, खाद्य पदार्थ, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैकेजिंग सामग्री, आर्किटेक्चरल पेंट, पाउडर कोटिंग, बैटरी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद्य योजक, लकड़ी के विकल्प, सौंदर्य प्रसाधन, एरोसोल और प्रोपेलेंट, प्लास्टिक उत्पाद, वस्त्र, अग्निशामक, चमड़ा और कॉयर उत्पाद सहित कई उत्पाद श्रेणियां शामिल हैं।

निष्कर्ष:

- उल्लेखनीय है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए भारत के प्रयास एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और लचीलेपन के लिए बुनियादी ढांचा बनाना है। ये कार्यक्रम और योजनाएं, जिसमें ग्रीन बॉन्ड और वनीकरण पहल जैसे वित्तीय साधन शामिल हैं, भारत के महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं, जिसमें वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन हासिल करने का देश का लक्ष्य शामिल है।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)



- इन प्रयासों की सफलता उनके सफल कार्यान्वयन, समुदाय की भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सहयोग पर निर्भर करेगी क्योंकि वे विकसित होते रहेंगे। ये कार्यक्रम एक ऐसे भविष्य के आधार बनेंगे जो पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल और लचीले दोनों हैं।
- भारत वर्ष 2023 और 2024 के लिए जो जलवायु नीतियां लागू कर रहा है वे पारिस्थितिकी बहाली और स्थिरता की दिशा में समुचित कदम हैं। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि पर्यावरण के ह्रास की कीमत पर आर्थिक विकास न हो और इसके लिए ग्रीन क्रेडिट योजना, गोबरधन और मिट्टी जैसे कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है।
- इन कार्यक्रमों में जलवायु लचीलापन के प्रति समग्र दृष्टिकोण को दर्शाया गया है जिसमें कार्बन बाजार, नवीकरणीय ऊर्जा और प्रकृति आधारित समाधान शामिल हैं और इनमें निजी और सरकारी दोनों तरह के उपक्रमों को शामिल करने का लक्ष्य है।
- चूंकि भारत अधिक दीर्घकालिक जलवायु की ओर अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये कार्यक्रम आर्थिक विकास और पर्यावरण की देखरेख के बीच संतुलन बनाने और विकसित भारत@2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

ADDRESS:

19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)